गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2022) के अवसर पर दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से प्रसारित राज्य की जनता के नाम
श्री फागू चौहान, महामहिम राज्यपाल, बिहार का संदेश

भाइयों, बहनों एवं प्यारे बच्चों,

राष्ट्र के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको एवं समस्त बिहारवासियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।

आज ही के दिन वर्ष 1950 में हमारा देश एक गौरवशाली संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और संसदीय व्यवस्था पर आधारित शासन की नींव रखी गई। संविधान के माध्यम से राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई है। संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा लोगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के सिद्धान्त हमारे पथप्रदर्शक हैं। इन्हीं के सहारे देश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पनायें पूरी हो रही हैं।

वर्तमान में भारत सहित पूरा विश्व कोरोना महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहा है। इस महामारी के कारण हमारा देश पिछले दो वर्षों से प्रभावित है। पिछले साल के अन्त तक देश में कोरोना का संक्रमण काफी कम हो गया था। बिहार में भी नये संक्रमण की संख्या लगभग नगण्य हो गई थी। परन्तु, इस वर्ष की शुरूआत से ही देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना के नये वैरियेंट ओमिक्रोन के आने से मामले अचानक तेजी से बढ़े हैं। इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार लोगों के साथ है। संक्रमण के उच्च दर को देखते हुए कोरोना जाँच की रफ्तार को बढ़ाया गया है। अबतक प्रति 10 लाख आबादी पर 5 लाख 55 हजार से अधिक जाँच हुई है और प्रतिदिन औसतन डेढ़ से दो लाख जाँच की जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार कोरोना पीड़ित लोगों को होम आईसोलेशन में रखा जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा मरीजों को आवश्यक दवाओं की मेडिकल किट एवं कॉल करके मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी के साथ आवश्यक चिकित्सीय परामर्श दिये जा रहे हैं। कोरोना के ईलाज के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर एवं कोविड केयर सेन्टर संचालित हैं जहाँ मरीजों के लिए पर्याप्त सामान्य बेड एवं ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध हैं।

कोरोना से बचाव के लिए राज्य में टीकाकरण का कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है। अब तक 18 वर्ष से ऊपर के 5 करोड़ 99 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीकाकरण की पहली डोज तथा 4 करोड़ 60 लाख से अधिक लाभार्थियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। 3 जनवरी, 2022 से 15 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू किया गया है और अब तक 35 लाख 51 हजार से अधिक बच्चों को टीकाकरण की पहली डोज दी गयी है। इन सबके बावजूद कोरोना से बचाव तभी संभव है जब हमलोग इसके प्रति सजग एवं सचेत रहेंगे और कोरोना से संबंधित सभी प्रकार के नियमों एवं दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है और सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। राज्य में कानून का राज स्थापित रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। राज्य में सामाजिक सौहार्द्र एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण है। साथ ही, सरकार द्वारा भ्रष्टाचार एवं आय से अधिक सम्पत्ति अथवा पदों के दुरूपयोग में संलिप्त भ्रष्ट लोक सेवकों तथा अवैध एवं अनैतिक तरीके से धनार्जन में संलिप्त माफिया तत्वों के विरूद्ध कठोर एवं प्रभावकारी कार्रवाई की जा रही है।

सरकार के द्वारा पिछले कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए लागू किये गये सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड, स्वंय सहायता भत्ता एवं कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ बिहार के युवक–युवतियों को मिल रहा है। हर घर तक बिजली पहुँचा दी गई है। हर घर तक नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली, शौचालय निर्माण एवं टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने संबंधी कार्य ज्यादातर पूरा हो चुके हैं तथा शेष कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है।

आधारभूत संरचना एवं मानव संसाधन के विकास की किरणें बिहार के कोने–कोने तक पहुँच रही हैं। बिहार में सड़कों तथा पुल–पुलियों का जाल बिछाकर, अब राज्य के सुदूर क्षेत्र से 5 घंटे में राजधानी पटना पहुँचने के लक्ष्य पर कार्य योजना बनाकर निर्माण कार्य चल रहा है।

शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास का कार्य कराया जा रहा है। पटना में मेट्रो रेल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों के पुनर्गठन एवं उत्क्रमण के फलस्वरूप इनकी संख्या 142 से बढ़कर 262 हो गयी है। साथ ही, नगर निगमों के मेयर/डिप्टी मेयर तथा नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के मुख्य पार्षद्/उप मुख्य पार्षद् का आम जनता द्वारा सीधा निर्वाचन की व्यवस्था की गयी है।

सरकार द्वारा बिजली के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाया गया है तथा बिजली के उत्पादन, संचरण एवं वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ स्मार्ट प्री–पेड मीटर लगाये जा रहे हैं तथा अब तक लगभग 4 लाख स्मार्ट प्री–पेड मीटर लगाकर यह राज्य देश में पहले स्थान पर बना हुआ है।

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई सृजन एवं बाढ़ नियंत्रण प्रभागों को अलग–अलग किये जाने के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। इससे बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हुआ है एवं बाढ़ नियंत्रण में भी काफी मदद मिली है।

बिहार की लगभग 85 प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है और लगभग 76 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं कृषि आधारित कार्यों पर निर्भर है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा कृषि रोड मैप बनाकर कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्तमान में तीसरे कृषि रोड मैप के तहत चलाये जा रहे कार्यक्रमों से कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि एवं किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिले, इसके लिए सरकार द्वारा पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से धान एवं गेहूँ की अधिप्राप्ति की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा मानव संसाधन की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए शिक्षा पर शुरू से ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक ओर जहाँ पोशाक, साईकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएँ लागू की गईं, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों के आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया। इसी का परिणाम है कि अब कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर पहुँच गयी है। सरकार द्वारा बालिका शिक्षा पर शुरू से ही जोर दिया गया है। बालिका शिक्षा का प्रजनन दर से बिल्कुल सीधा संबंध है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया।

राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005–06 में जहां शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 61 थी, वह अब घटकर 32 हो गई है जो पहली बार राष्ट्रीय औसत के बराबर है। इस दौरान टीकाकरण 18 प्रतिशत से बढ़कर 86 प्रतिशत, मातृ मृत्यु दर प्रति लाख पर 312 से घटकर 149 एवं कुल प्रजनन दर 4.3 से घटकर 3 प्रतिशत पहुँच गयी है। अस्पतालों में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना का विकास हुआ है एवं कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को

5 हजार 462 बेड की क्षमता वाले आधुनिक विश्वस्तरीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों का निःशुल्क उपचार हेतु ''बाल हृदय योजना'' लागू की गयी है जिसके तहत अब तक 220 बच्चों का प्रशान्ति फाउंडेशन के सहयोग से अहमदाबाद के सत्यसाईं अस्पताल में ईलाज कराया गया है।

राज्य सरकार द्वारा समाज सुधार के कार्यक्रम लगातार चलाये जा रहे हैं। सबसे पहले शराबबंदी लागू कर सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई। समाज सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के विरूद्ध राज्यव्यापी अभियान चलाया गया जिसको लोगों का पूरा समर्थन मिला है।

राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही वंचित वर्गों के लिए काम किया गया तथा इन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं चलाई गईं। सरकार ने महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया है तथा महिलाओं को रोजगार देने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी आयामों पर काम किया जा रहा है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तर्ज पर सभी वर्गो की महिलाओं को उद्यमी योजना के तहत 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रूपये का अनुदान एवं 5 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। जीविका के अंतर्गत अब तक 10 लाख 31 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 1 करोड़ 27 लाख से भी अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावास अनुदान योजना एवं सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का सफल संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत हर पंचायत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 4 तथा अतिपिछड़ा वर्ग के 3 युवाओं को लाभ दिया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के लिए विद्यार्थी प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, रोजगार ऋण, कौशल विकास, महिला परित्यक्ता सहायता, मुफ्त कोचिंग आदि योजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है। मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना एवं अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना भी संचालित हैं। बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के तहत पटना सहित 5 जिलों में सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं शिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बहुदेश्शीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, वक्फ कार्यालय भवन, मार्केट कॉम्पलेक्स आदि का निर्माण/पुनर्निर्माण किया जा रहा है।

राज्य सरकार बिहार में उद्योगों के विकास के लिए तत्पर है। राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई संशोधित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2020 लागू की गई है। कृषि एवं काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु नई नीति बनाई गई है। मक्का एवं गन्ना के किसानों की आय बढ़ाने हेतु विशेष इथेनॉल नीति लाई गई है।

राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित है तथा इसके लिए जल–जीवन–हरियाली अभियान के सभी अवयवों पर मिशन मोड में काम हो रहा है। राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए इस अभियान के तहत पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। बिहार विभाजन के उपरान्त राज्य में हरित आवरण मात्र 9 प्रतिशत रह गया था जो अब लगभग 15 प्रतिशत हो गया है। राज्य में हरित आवरण के लक्ष्य को बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया गया है जिसके लिए सरकार प्रयासरत हैं।

सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे तथा पर्यावरण का संरक्षण हो और राज्य को कोरोना संक्रमण की महामारी से मुक्ति मिले। हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। आइये, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि बिहार को विकसित एवं खुशहाल राज्य बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार पुनः आप सबको अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ। जय हिन्द!

***